नईदुनिया

होर्मुज तनाव, कच्चा तेल और अमेरिकी नीतिगत संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल

अमेरिकी एफओएमसी के ब्योरे से लेकर चीन के आर्थिक आंकड़े तक, इन पर रहेगा बाजार का फोकस

मुंबई

इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार की दिशा होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव, अमेरिका-ईरान संबंधों में अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निर्धारित होगी। विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक जारी होने वाले अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के ब्योरे और चीन के आर्थिक आंकड़ों पर भी पैनी निगाह रखेंगे। बीते सप्ताह स्थानीय बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब वैश्विक घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित हो गया है। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन समाप्त होने के बाद अब निवेशकों का ध्यान घरेलू कारकों से हटकर वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों पर केंद्रित हो गया है। रिलायंस ब्रोकिंग के एक अधिकारी ने बताया कि निकट अवधि में होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रम और ब्रेंट कच्चे तेल की दिशा बाजार के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आने वाला सप्ताह आंकड़ों के लिहाज से अपेक्षाकृत हल्का है, ऐसे में वैश्विक मौद्रिक नीति, कच्चे तेल की कीमतें और भू-राजनीतिक स्थिति ही बाजार को दिशा देंगी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक का ब्योरा 19 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत रुख को लेकर अहम संकेत मिलेंगे।

यदि फेडरल रिजर्व का रुख अपेक्षा से अधिक आक्रामक दिखाई देता है, तो इससे उभरते बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी बढ़ सकती है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ जाएगा। बाजार के जानकारों ने कहा कि निवेशक कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका-ईरान के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव से जुड़े घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखेंगे। कच्चा तेल, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, एफओएमसी की बैठक का ब्योरा और चीन के आर्थिक आंकड़े इस सप्ताह बाजार को दिशा देने वाले प्रमुख संकेतक होंगे। इनसे वैश्विक आर्थिक वृद्धि और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर आगे की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।

न्यूज ब्रीफ

शीर्ष 10 कंपनियों में से पांच का बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ घटा, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान अभी भी नंबर वन पर

मुंबई। बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा, जिसके चलते सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से पांच के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में सामूहिक रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपये की बड़ी कमी आई। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को इस दौरान सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा। समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.62 प्रतिशत और एनएसई निफ्टी 0.83 प्रतिशत के नुकसान में रहा। इस गिरावट का असर शीर्ष कंपनियों पर स्पष्ट दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में कमी दर्ज की गई। इन पांच कंपनियों के बाजार मूल्य में कुल मिलाकर करीब एक लाख करोड़ रुपये की कमी हुई। टीसीएस का मार्केट कैप सर्वाधिक 34,263.28 करोड़ रुपये घटकर 8.53 लाख करोड़ रुपये रह गया। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 31,869.13 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का मूल्यांकन 25,891.88 करोड़ रुपये घट गया।

दिल्ली के भाइयों ने वालेंटियर या> ा से गांवों को बदला, बनाया 1 करोड़ का स्टार्टअप

नई दिल्ली। दिल्ली के दो साधारण भाइयों आकाश मान और करुणेश मान ने एक अनूठे आइडिया को सफल व्यवसाय में बदल दिया है। उनके स्टार्टअप वालेंटियर यात्रा ने शहरों के हुनरमंद प्रोफेशनल्स को गांव के होमस्टे, स्कूलों और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स से जोड़कर ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला दी है। इस प्लेटफार्म के जरिए प्रोफेशनल्स गांवों में मुफ्त रहने-खाने का आनंद लेते हैं, बदले में ग्रामीण समुदायों को अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं। आज यह कंपनी 1 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्यू तक पहुंच गई है और गांवों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की सेवाएं दे चुकी है। लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले आकाश और करुणेश के पिता डीटीसी में बस कंडक्टर थे। कालेज के दिनों में फोटोग्राफी और मार्केटिंग में हाथ आजमाने के बाद, साल 2020 के कोरोना लाकडाउन ने उन्हें एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। हिमाचल के एक होमस्टे मालिक की मुफ्त आनलाइन मार्केटिंग करके उन्होंने बदले में जिंदगीभर मुफ्त रहने-खाने का न्योता पाया। इसी घटना ने उन्हें वालेंटियर यात्रा का विचार दिया- क्यों न शहरों के हुनरमंदों को गांवों से जोड़ा जाए, जहां यात्री मुफ्त में रहें और बदले में स्थानीय व्यवसायों को आगे बढ़ाएं।

पूर्वोत्तर में पर्यटन क्रांति, अरुणाचल का मेचुखा बनेगा नया आकर्षण का केंद्र

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.22 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। केरल और गोवा जैसे राज्यों के नक्शेकदम पर अब पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश भी पर्यटन को गति देने में जुट गया है। राज्य सरकार अब ईटानगर और तवांग से परे अपनी अनछुई सुंदरता, खासकर मेचुखा घाटी, को दुनिया के सामने लाना चाहती है। राज्य के पर्यटन मंत्री पसांग दोर्जी सोना ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुषमा और विशाल क्षेत्रफल (83,743 वर्ग किमी) के लिए जाना जाता है, अब पर्यटकों को दूर-दराज के मनोरम स्थलों तक पहुंचाना चाहता है। इसी क्रम में भूटान और चीन (तिब्बत) सीमा से लगी मेचुखा घाटी को विशेष रूप से प्रचारित किया जा रहा है। मेचुखा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेचुखा ट्राउट क्वेस्ट 2.0 की सफल मेजबानी की, जिसमें थाईलैंड और भूटान सहित कई देशों के 56 एंगलर्स ने भाग लिया।

लागत से नीचे बिक्री से सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन तेलों में गिरावट, सरसों भी प्रभावित

आयातकों द्वारा बैंक कर्ज चुकाने का दबाव सरकारी बैंकों और किसानों के लिए चिंता का विषय

नई दिल्ली

बीते सप्ताह देश के खाद्य तेल बाजार में आयातकों द्वारा लागत से नीचे दाम पर की गई बिकवाली के कारण बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोयाबीन, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलिन जैसे आयातित खाद्य तेलों में लगातार गिरावट बनी रही, जिससे घरेलू बाजार की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई और सरसों तेल के दाम भी नीचे आए।

इस बिक्री के पीछे आयातकों द्वारा बैंक कर्ज चुकाने का दबाव बताया जा रहा है, जो सरकारी बैंकों और अंतत: किसानों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। आयातित तेलों के 22-28 रुपये प्रति किलो सस्ते होने के कारण घरेलू मांग कमजोर रही। इसका असर मूंगफली तेल-तिलहन पर भी पड़ा, जिनकी कीमतें स्थिर रहीं। सरसों तिलहन और तेल में भी कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि किसान कम दाम पर बेचने को तैयार नहीं थे और ऊंचे भाव पर तेल खप नहीं रहा था। इसके विपरीत केवल बिनौला तेल में ब्रांडेड कंपनियों की बढ़ती मांग और कम उपलब्धता के कारण तेजी दर्ज की गई। सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 8,300-8,350 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना रहा।

जबकि सरसों तेल दादरी 25 रुपये की गिरावट के साथ 16,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल भी क्रमश: 5-5 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 2,725-2,825 रुपये और 2,725-2,875 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमश: 400-400 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 6,900-6,950 रुपये और 6,750-6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार दिल्ली में सोयाबीन तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 15,675 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 15,525 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 100 रुपये की गिरावट के साथ 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 7,350-7,925 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 17,000 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,680-2,980 रुपये प्रति टिन पर स्थिर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम भी 100 रुपये की गिरावट के साथ 13,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 75 रुपये की गिरावट के साथ 15,575 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 75 रुपये की गिरावट के साथ 14,325 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। ब्रांडेड कंपनियों की औद्योगिक मांग बढ़ने और उपलब्धता कम रहने के बीच एकमात्र बिनौला तेल का दाम 200 रुपये के सुधार के साथ 17,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह सरसों दाना 8,300-8,350 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना रहा।

जबकि सरसों तेल दादरी 25 रुपये की गिरावट के साथ 16,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल भी क्रमश: 5-5 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 2,725-2,825 रुपये और 2,725-2,875 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमश: 400-400 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 6,900-6,950 रुपये और 6,750-6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार, दिल्ली में सोयाबीन तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 15,675 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 15,525 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 100 रुपये की गिरावट के साथ 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 7,350-7,925 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 17,000 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,680-2,980 रुपये प्रति टिन पर स्थिर बंद हुआ।

सीपीओ तेल का दाम भी 100 रुपये की गिरावट के साथ 13,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 75 रुपये की गिरावट के साथ 15,575 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 75 रुपये की गिरावट के साथ 14,325 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। ब्रांडेड कंपनियों की औद्योगिक मांग बढ़ने और उपलब्धता कम रहने के बीच एकमात्र बिनौला तेल का दाम 200 रुपये के सुधार के साथ 17,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

सरकारी खरीद में महंगाई का नया पैमाना, डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई अपनाने का निर्देश

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने अपनी खरीद प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव की पहल की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को भविष्य के सरकारी अनुबंधों में मूल्य-वृद्धि और दर समायोजन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकारी ठेकों में लागत समायोजन को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

व्यय विभाग ने पिछले माह एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर मंत्रालयों और विभागों को पीपीआई उपलब्ध होने पर इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। सरकार का मानना है कि पीपीआई उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से स्वीकृत सूचकांक है। यह कदम परियोजना के दौरान सामग्री, श्रम और ईंधन जैसी प्रमुख लागत में बदलाव के अनुसार भुगतान समायोजन सुनिश्चित करेगा, जिससे सरकार और ठेकेदार दोनों के लिए महंगाई के प्रभाव को साझा करने में मदद मिलेगी। भारत में वाणिज्य मंत्रालय ने जून 2023 से वस्तुओं और सेवाओं के लिए मासिक पीपीआई आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है। वस्तुओं के पीपीआई में विनिर्मित उत्पादों का सर्वाधिक 69.93 प्रतिशत भारांश है, जबकि कृषि, बिजली और खनन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, रेलवे, हवाई यात्री सेवाओं और दूरसंचार सहित सात प्रमुख सेवाओं को पहले चरण में शामिल किया गया है। यह पहल भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रणाली के अनुरूप लाएगी और डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की ओर संभावित दीर्घकालिक बदलाव का संकेत देती है।

इंडियन बैंक कारोबार विस्तार हेतु जुटाएगा 1 अरब डालर

चेन्नई। सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन बैंक अपने कारोबार विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस सप्ताह बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के माध्यम से 40 करोड़ डालर जुटाने के लिए तैयार है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक की कुल योजना ईसीबी से लगभग एक अरब डालर और विदेशी मुद्रा प्रवासी (एफसीएनआर-बी) जमा से लगभग दो अरब डालर जुटाने की है, जिसमें से 1.5 अरब डालर पहले ही प्राप्त हो चुका है। अधिकारी के अनुसार, बैंक दिसंबर 2026 तक भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती अदला-बदली सुविधा का लाभ उठाते हुए अतिरिक्त 60 करोड़ डालर भी जुटा सकता है। एफसीएनआर-बी जमा के बेहतर प्रवाह को देखते हुए, आरबीआई ने निर्धारित समय से पहले ही विशेष डालर-रुपया विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा के तहत जमा जुटाने की अवधि समाप्त कर दी है। हालांकि, ईसीबी और अन्य विदेशी मुद्रा उधारी के लिए समयसीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बनी हुई है। वित्तीय विस्तार के साथ, इंडियन बैंक ने हाल ही में अपनी 120वीं स्थापना दिवस (15 अगस्त को) मनाया। इस अवसर पर, बैंक ने देश भर में 15 नई शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए आईबी साइबर कैप्टन नामक एक शुभंकर पेश किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से तीन भाषाओं में वायस बैंकिंग सेवा सहित कई नई डिजिटल पहल भी शुरू कीं।

अंबर एंटरप्राइजेज बनाएगी ओप्पो, वनप्लस और रियलमी के स्मार्टफोन

मार्च 2027 से भारत में शुरू होगा विनिर्माण, पहले साल 80 लाख यूनिट बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली

इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सेवा कंपनी अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया चीन के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो, वनप्लस और रियलमी के लिए भारत में मोबाइल फोन का विनिर्माण मार्च 2027 की तिमाही से शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी के कार्यकारी एक प्रमुख अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। यह कदम भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों के एसेट-लाइट विनिर्माण माडल की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण संकेत है, जहां कंपनियां उत्पादन के लिए स्थानीय इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों पर अधिक निर्भर हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में परीक्षण उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही में व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी। अंबर एंटरप्राइजेज पहले वर्ष में लगभग 80 लाख स्मार्टफोन बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से दूसरे वर्ष में 1.5 से 1.6 करोड़ इकाई तक बढ़ाया जाएगा।

मोबाइल फोन कारोबार के लिए कंपनी ने एक मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) की नियुक्ति भी की है। ओप्पो मोबाइल्स इंडिया के साथ हुआ यह विनिर्माण सहयोग समझौता ओप्पो, वनप्लस और रियलमी तीनों ब्रांडों के लिए है। यह भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांडों द्वारा अपनी प्रत्यक्ष विनिर्माण हिस्सेदारी कम करते हुए उत्पादन के लिए स्थानीय कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाने की रणनीति को दर्शाता है। अंबर के पीसीबी कारोबार में कापर-क्लैड लैमिनेट (सीसीएल) की कीमतों में वृद्धि से मार्जिन पर दबाव पड़ा है, जिसकी लागत वह ग्राहकों पर डाल रही है। कंपनी 2029-30 तक अपना सीसीएल संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बना रही है।

यूनिटेक में 15,000 घर खरीदार फंसे, 15 साल की देरी ! एसी से जल्द समाधान की गुहार

खरीदारों ने खाली संपत्तियों की नीलामी और तत्काल नए सीएमडी की मांग की

नई दिल्ली

संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड की अटकी परियोजनाओं से जुड़े हजारों घर खरीदारों ने निर्माण कार्यों के लिए धन की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार और उच्चतम न्यायालय से कंपनी की खाली पड़ी संपत्तियों की नीलामी कर परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। साथ ही, खरीदारों ने कंपनी के लिए नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की नियुक्ति जल्द करने की भी अपील की है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पद पिछले एक महीने से खाली पड़ा है। यूनिटेक में सीएमडी का पद पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक युधवीर सिंह मलिक के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने नए सीएमडी के लिए नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की मंजूरी का इंतजार है। खरीदार संगठनों का मानना है कि इस पद पर नियुक्ति में देरी परियोजनाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है। दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में यूनिटेक की आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में लगभग 15,000 खरीदार फंसे हुए हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं 15 साल से अधिक की देरी से चल रही हैं।

गुरुग्राम स्थित एस्पेस प्रीमियर ओनर्स एसोसिएशन जैसी कई खरीदार संघों का कहना है कि उन्हें अपने घरों का 16 साल से अधिक समय से इंतजार है। खरीदारों का अनुमान है कि सभी अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 11,000-12,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि ग्राहकों से केवल 3,000 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सकते हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2,455.73 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा दर्ज किया था।

यूनिवर्ल्ड चेन्नई ओनर्स एसोसिएशन और एल्डर ग्रोव विला ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने ऋणदाताओं के दावों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन पर ब्याज भुगतान रोकने का भी आह्वान किया है। एंथिया फ्लोर्स खरीदार संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 2005 के बाद यूनिटेक को दिए गए कर्ज का विशेष आडिट कराने की मांग की है, ताकि संभावित खामियों की पहचान कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके। कोलकाता स्थित यूनिवर्ल्ड सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसायटी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले में खरीदारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2020 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनिटेक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था।